**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 111

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी**

**\***111. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों की कमी के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी के क्या कारण हैं और ये रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

 **मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**'ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी' के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा दिनांक 20.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 111 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।**

(क) से (ग): उच्‍चतर शिक्षा के मानकों में सुधार एक निरंतर चलने वाला प्रयास है और केंद्र सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सरकार ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनका लक्ष्‍य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भारतीय विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करना है।

एआईएसएचई 2016-17 रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 19732 कॉलेज हैं। ग्रामीण कॉलेजों में 680924 संस्‍वीकृत पद हैं, जिसमें से 543626 पद भरे हैं। रिक्‍त पदों की स्थिति संस्‍वीकृत संख्‍या का 20.1 प्रतिशत तक है। ग्रामीण कॉलेजों में रिक्‍त पदों को भरना राज्‍य सरकार/विश्‍वविद्यालों के क्षेत्राधिकार में आता है।

केंद्र सरकार ने देश में उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विश्‍वविद्यालय/कॉलेज भी शामिल हैं:

(i) विश्‍वविद्यालयों को विश्‍वविद्यालय में कुल संकाय पदों के 10 प्रतिशत तक उनकी कार्यात्‍मक आवश्‍यकताओं के आधार पर, समय-समय पर रिक्‍त पदों के विरूद्ध तदर्थ/अतिथि संकाय/पुनर्नियोजित/संविदा संकाय की भर्ती करने की अनुमति है। यूजीसी ने शैक्षिक संस्‍थाओं में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक संकाय को पैनलबद्ध करने के लिए दिर्शानिर्देश भी जारी किए हैं। ये संस्‍थाएं किसी भी समय कुल स्‍वीकृत संकाय संख्‍या के 25% तक सहायक संकाय नियुक्‍त कर सकती हैं।

(ii) प्रतिभावान और अर्हताप्राप्‍त संकाय की भर्ती करने, बनाए रखने के लिए और उन्हें ऐसे वातावरण और कार्य स्थितियां उपलब्‍ध कराने हेतु जिसमें उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्‍हें प्रोत्‍साहित किया जा सके, केंद्र सरकार ने विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्‍य शैक्षिक कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया है जो उत्‍कृष्‍ट गुणवत्‍ता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने में सहायता करेगा। इस वेतनमान के ऊर्ध्‍वगामी संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों के विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

(iii) उच्‍चतर शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए, सरकार ने एक परियोजना अर्थात स्‍टडी वेब्‍स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स (स्‍वयम) शुरू की जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देशभर के विद्यार्थियों को व्‍यापक मुक्‍त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक) उपलब्‍ध कराने की दृष्टि से उन्‍हें पहुंच, समानता और गुणवत्‍ता को प्रोत्‍साहन मिल सके।

(iv) इसके अतिरिक्‍त, उच्‍चतर शिक्षा को पहुंच योग्‍य और वहनीय बनाने के लिए, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुक्‍त और दूरस्‍थ अध्‍ययन के लिए विनियमन लाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। यह असेवित, अल्‍पसेवित और शैक्षणिक रूप से लाभवंचित स्‍थानों में रहने वाले प्रशिक्षुओं के लिए उपयुक्‍त गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा उपलब्‍ध कराएगा।

(v) इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े और आकांक्षी जिलों में 130 नए मॉडल डिग्री कॉलेज स्‍थापित करने के लिए सहायता प्रदान की है। सरकार ने 106 वर्तमान डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजों में स्‍तरोन्‍नत करने के लिए सहायता भी प्रदान की है।

(vi) रूसा के तहत, 2013-14 से 2014-15 तक 723.47 करोड़ रूपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई थी। अब इस निधि को 2015-16 से 2019-20 तक 9489.03 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, रूसा के तहत आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है।

(vii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान और राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान से 1700 पीएच.डी स्‍नातक भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्‍ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्‍यूआईपी) के तहत तकनीकी और इंजीनियरिंग उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य में लगे हुए हैं।

**\*\*\*\*\***